पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बोर्ड का गठन

1588. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या योजना और कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद जिलों के प्रखण्डों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिये एक बोर्ड गठित किये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध वर्ष 1987–88 के चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति घरेलू खपत के जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि फैजाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी डिविजनों के 14 जिलों में से 10 के आंकड़ें राज्य के अधिकांश जिलों के आंकड़ों के सदृश्य हैं ।

(ख) क्षेत्र तथा आयोजना का विकास और उस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

Joint venture proposals for acquisition of deep sea fishing: trawlers

1589. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether 180 joint venture proposals envisaging acquisition and operation of deep sea fishing trawlers are pending for consideration and decision by Government; and

(b) if so, the reasons for not arriving at a decision as the delay-adversely affects the enormous export potential of deep sea fishing industry?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Ten proposals for entering into joint venture in deep sea fishing by Indian companies are pending at present. These proposals would be considered by an Empowered Committee of Secretaries in their next meeting. A decision on the propoals will be taken thereafter.

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य

1590. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2000 के अंत तक 10,000 मेगावाट परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल के आर्थिक संकट के कारण इस लक्ष्य में संशोधन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन का अब क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा मार्च, 1991 के अंत में देश में परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन की कुल कितने मेगावाट टन की अधिष्ठापित क्षमता थी और क्या यह उत्पादन, क्षमता के अनुरूप रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1990–91 में क्षमता की तुलना में उत्पादन की प्रतिशतता कितनी थी ; और